एक्ज़िम बैंक EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस
निर्यात लाभ

जून 2018
खंड XXXIV अंक II

इस अंक में

1-3 बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत के सीमाई व्यापार को बढ़ाना
4 टेक्निकल टेक्सटाइल
5 चीन के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध
6 लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई क्षेत्र में निवेश
7 इस्पात उद्योग
8 भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध
9 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
10 तिमाही गतिविधियां
11 ब्याज दर परिदृश्य
12 एक्ज़िम बैंक की गतिविधियां
13 देशों का सूक्ष्मावलोकन
14 मुद्रा की प्रवृत्तियां
15 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य
16 व्यापार और भागीदारी अवसर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

मुख्य कार्यालय :
केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400 005
Tel.: 022 2217 2600
Email : ccg@eximbankindia.in

बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत के सीमाई व्यापार को बढ़ाना

भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने तथा रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बेहतर संपर्क स्थापित किया जा सके। वस्तुतः, भारत के पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों के निकटतम सीमावर्ती देश 'एक्ट ईस्ट नीति' की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। म्यांमार, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) का एकमात्र सदस्य देश है, जिसकी सीमा भारत के चार राज्यों- मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगभग 1,643 किलोमीटर तक लगी हुई है। भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' की सफलता के लिए बांग्लादेश भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी 4,096.7 किमी लंबी सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगी हुई है।

बांग्लादेश भारत, म्यांमार श्रीलंका और थाइलैंड तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) में आने वाले देशों, यथा बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का क्षेत्रीय सहयोग भी निरंतर प्रासंगिक होता जा रहा है। बिम्सटेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिणपूर्व एशिया के बीच एक सेतु का कार्य करता है। साथ ही सार्क और आसियान सदस्यों के बीच अंतर-क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग हेतु एक सामान्य प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार

दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2017 में भारत के कुल निर्यात का 37.5 प्रतिशत तथा भारत के कुल आयात का 20 प्रतिशत व्यापार दक्षिण एशिया से किया गया। पिछले दशक में, भारत-बांग्लादेश व्यापार, लगभग दोगुनी वृद्धि करते हुए वर्ष 2008 के 3.6 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 6.3 अरब यूएस डॉलर तक पहुँच गया। पिछले दशक में, भारत का बांग्लादेश को निर्यात, 6.7 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि करते हुए वर्ष 2008 के 3.2 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 5.8 अरब यूएस डॉलर तक पहुँच गया, जबकि बांग्लादेश से भारत द्वारा आयात 3.8 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज करते हुए वर्ष 2008 के 329.8 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 459.4 मिलियन रहा। बांग्लादेश के साथ भारत का व्यापार अधिशेष वर्ष 2008 के 2.9 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 5.3 अरब यूएस डॉलर हो गया।

वर्ष 2017 में भारत द्वारा बांग्लादेश (बांग्लादेश में भारत के कुल निर्यात का 20 प्रतिशत) को निर्यात की जाने वाली प्रमुख कमॉडिटी कपास रही, इसके बाद रेलवे, अनाज, खनिज ईंधन और मशीनरी के अतिरिक्त वाहन भी प्रमुख निर्यात सामग्री में शामिल रहे। वर्ष 2017 में बांग्लादेश से भारत द्वारा आयात की गई वस्तुओं में वेजीटेबल टेक्सटाइल फाइबर, पेपर यार्न और बुने हुए कपड़े शामिल थे, जो कुल आयात का 20.7 प्रतिशत भाग था। इसके अतिरिक्त अन्य आयातित सामग्री में परिधान एवं वस्त्र, नमक, सल्फर व सीमेंट तथा लेड व अन्य वस्तुएं शामिल रहीं।

भारत-म्यांमार द्विपक्षीय व्यापार

भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार में हाल ही के कुछ वर्षों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2008 के 1.1 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 1.2 अरब यूएस डॉलर से भी अधिक हो गया। वर्ष 2015 तक व्यापार घाटे के बाद हाल के कुछ वर्षों में भारत ने म्यांमार के साथ अपना व्यापार अधिशेष बनाए रखा है, जो म्यांमार से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सब्जियों, कंद-मूल और लकड़ी के उत्पादों के आयात में कमी को प्रदर्शित करता है।

म्यांमार को भारत द्वारा निर्यात 12.5 प्रतिशत की सीएजीआर की वृद्धि करते हुए वर्ष 2008 के 237.3 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 685.9 मिलियन यूएस डॉलर का रहा , जबकि भारत द्वारा म्यांमार से आयात वर्ष 2008 के 906.3 मिलियन यूएस डॉलर से घटकर वर्ष 2017 में 578.3 मिलियन यूएस डॉलर रह गया। वार्षिक आधार पर, वर्ष 2017 में म्यांमार को भारत द्वारा निर्यात और म्यांमार से भारत द्वारा आयात में क्रमश: 39.9 प्रतिशत और 46.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

म्यांमार को भारत द्वारा निर्यातित सामग्री में अन्य के साथ-साथ मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल उत्पाद, लौह और इस्पात, चीनी और चीनी कन्फेक्शनरी, विद्युत मशीनरी व उपकरण तथा वाहन शामिल रहे। म्यांमार को भारत द्वारा कुल निर्यात का 51.8 प्रतिशत हिस्सा इसी सामग्री का रहा। वर्ष 2017 में म्यांमार से भारत द्वारा आयातित वस्तुओं में खाद्य सब्जियों, कंद-मूल तथा लकड़ी के उत्पादों का 91 प्रतिशत हिस्सा रहा। वस्तुतः, वर्ष 2017 में खाद्य सब्जियों और लकड़ी के उत्पादों के लिए आयात के संबंध में म्यांमार, भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा स्रोत रहा।

बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा व्यापार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016-17 में बांग्लादेश को भारत का 46.5 प्रतिशत निर्यात ट्रक के माध्यम से, 0.5 प्रतिशत रेलवे के माध्यम से तथा शेष 53 प्रतिशत समुद्र या हवाई मार्ग द्वारा किया गया। आईसीपी पेट्रापोल बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, जिसके माध्यम से वर्ष 2016-17 में कुल निर्यात का 34 प्रतिशत और आयात का 58 प्रतिशत लेनदेन किया गया। बंदरगाह-वार विश्लेषण यह दर्शाता है कि आईसीपी पेट्रापोल, न्हावा शेवा (समुद्र), मुंद्रा, घोजदंगा तथा चेन्नै (समुद्र) शीर्ष 5 बंदरगाह हैं, जिनके माध्यम से वर्ष 2016-17 में बांग्लादेश को 60 प्रतिशत निर्यात किया गया।

बांग्लादेश से आयातित माल का एक बड़ा हिस्सा भारत-बांग्लादेश सीमा पर भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) के माध्यम से भारत में ट्रक द्वारा प्रवेश करता है। इसका लगभग तीन-चौथाई आयात भूमि मार्ग और पांचवां भाग समुद्र मार्ग से होता है, जबकि 2.6 प्रतिशत रेल मार्ग से तथा एक प्रतिशत से भी कम भाग वायु मार्ग से आयात किया जाता है। वर्ष 2016-17 में बांग्लादेश से आयात किए जाने वाले स्थानों में से शीर्ष 5 बंदरगाह पेट्रापोल (भूमि), तुतिकोरिन, घोजदंगा (भूमि), मोहेदीपुर (भूमि) तथा न्हावा शेवा (समुद्र) रहे, जिनके माध्यम से बांग्लादेश से भारत के कुल आयात का 75 प्रतिशत भाग आयात हुआ।

भूमि सीमा शुल्क स्टेशन: भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार, मुख्यत: सीमा से संबद्ध 49 भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) और 2 एकीकृत चेक पोस्टों (आईसीपी) के माध्यम से किया जाता है। इस समय 49 एलसीएस में से 37 परिचालन में हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर एलसीएस माल और यात्रियों के लिए पारगमन, सीमा शुल्क और आप्रवासन और कार्गो हैंडलिंग जैसी सेवाएं प्रदान करता है। पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल) और अगरतला (त्रिपुरा) में स्थित एलसीएस को आईसीपी के रूप में विकसित किया गया। अगस्त 2017 से सीमा पार कार्गो आंदोलन के समर्थन में, आईसीपी पेट्रापोल को सातों दिन 24 घंटे, सीमा शुल्क निकासी की सुविधा के साथ संचालित किया गया।

बॉर्डर हाट: अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश में बॉर्डर हाट के पुन: संचालन पर सहमति बन गई। बॉर्डर हाट में व्यापार के लिए सीमित उत्पाद होते हैं, जिन्हें बाजार के लिए तय की गई व्यापार सीमा के अनुसार केवल प्रमाणित विक्रेता (आमतौर पर सीमा के आसपास के जिलों के निवासी) ही बेच सकते हैं। वर्तमान में चार बॉर्डर हाट (त्रिपुरा में श्रीनगर और कमलासागर तथा मेघालय में कालीचार और बालाट) परिचालन में हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार भारत एवं बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हाट के माध्यम से लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार होता है।

म्यांमार के साथ भारत का सीमा व्यापार

वाणिज्य मंत्रालय, म्यांमार सरकार के अनुसार, भारत और म्यांमार के बीच सीमा व्यापार वर्ष 2011-12 के 15.4 मिलियन यूएस डॉलर से छह गुना बढ़कर वर्ष 2016-17 में 88.2 मिलियन यूएस डॉलर हो गया। तथापि, साइनो-म्यांमार तथा थाई-म्यांमार सीमा व्यापार की तुलना में भारत-म्यांमार सीमा व्यापार अपेक्षाकृत कम रहता है। न्हावा शेवा (जेएनपीटी) म्यांमार का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, जिसके द्वारा वर्ष 2016-17 में कुल निर्यात का 19.3 प्रतिशत तथा आयात का 58 प्रतिशत व्यापार किया गया। न्हावा शेवा (समुद्र), कोलकाता (समुद्र), मुंद्रा, चेन्नै (समुद्र) और दिल्ली (आईसीडी) शीर्ष 5 बंदरगाह हैं, जिनके द्वारा वर्ष 2016-17 में म्यांमार को 53.5 प्रतिशत निर्यात किया गया। म्यांमार से आयात मुख्य रूप से चेन्नै (समुद्र), न्हावा शेवा (समुद्र), तुतिकोरिन (समुद्र), जीएमआर हैदराबाद एविएशन लिमिटेड एसईजेड, कोलकाता (समुद्र) और कोच्चि (समुद्र) के माध्यम से किया गया। म्यांमार से कुल आयात का 88 प्रतिशत इन्हीं बंदरगाहों द्वारा हुआ। वर्ष 2016-17 में म्यांमार से भारत के कुल आयात का 1.7 प्रतिशत हिस्सा मोरे के माध्यम से आयात किया गया, जबकि जोखावथर के माध्यम से कोई प्रमुख आयात नहीं हुआ।

शुरुआत में वस्तु-विनिमय को क्षेत्रीय उत्पादित वस्तुओं के आदान-प्रदान हेतु भारत-म्यांमार सीमा पर सीमा व्यापार के रूप में अनुमति प्रदान की गई थी। तथापि, ये लेनदेन बैंकिंग प्रणाली में अंकित नहीं किए गए और न ही इन्हें व्यापार संबंधी आंकड़ों में दर्शाया गया। बीतते समय के साथ व्यापार का विशाखन हुआ तथा सामान्य व्यापार को सहयोग के लिए ऐसे लेनदेनों का लेखा-जोखा दर्ज करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर, 2015 से भारत-म्यांमार सीमा व्यापार समेत व्यापार संबंधी अन्य सभी लेनदेनों को एशियन क्लीयरिंग यूनियन मैकेनिज्म सहित किसी भी अनुमत मुद्रा में निपटाना अनिवार्य कर दिया।

भूमि सीमा शुल्क स्टेशन: वर्तमान में, म्यांमार के साथ सीमा व्यापार से संबंधित लेन-देन करने के लिए भारत में दो भूमि सीमा शुल्क स्टेशन हैं। इनमें से एक मणिपुर के मोरे में है, जो म्यांमार के तमू में स्थित भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के साथ लेन-देन करता है तथा दूसरा मिजोरम के जोखावथर में है, जो म्यांमार के रीह में स्थित भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के साथ लेन-देन करता है। तीसरा स्टेशन म्यांमार के सोमारा के साथ लेनदेन करने हेतु नागालैंड के अवंगखु में शुरू होने जा रहा है, इसे दोनों पक्षों की सहमति प्राप्त है, लेकिन इसे अभी तक भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। मिजोरम के लॉन्गत्लाई जिले में जोरिनपुई को एक नए भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के लिए चुना गया। साथ ही मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा को कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना (केएमएमटीटीपी) के लिए चुना गया। मोरे पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के बीच सबसे सक्रिय है, जहां से म्यांमार के साथ भारत के सीमा व्यापार का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य होता है। यातायात साधनों की बढ़ती संख्या से संबंधित समस्या के निवारण हेतु भारत सरकार इस स्टेशन को एकीकृत चेक-पोस्ट (आईसीपी) के रूप में उन्नत कर रही है।

बॉर्डर हाट: सीमा के पास रहने वाले समुदायों की आवश्यकताओं को समझते हुए, भारत और म्यांमार ने बॉर्डर हाट स्थापित करने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने म्यांमार सरकार के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) किया, जिसके अंतर्गत पारस्परिक रूप से सहमति प्रदान किए गए नौ स्थानों पर बॉर्डर हाट स्थापित किए जाएंगे। हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, बॉर्डर हाट स्थापित करने की प्रक्रिया पर आधिकारिक प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद पहला हाट सागाईंग क्षेत्र के नजदीक पंग्सू पास तथा अरुणाचल प्रदेश में प्राथमिक परियोजना के रूप में स्थापित किया जाएगा।

बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत के सीमा व्यापार को बढ़ाने हेतु रणनीतियां

सीमा संबंधित बुनियादी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता: भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच वस्तुओं के सीमा-पार परिवहन को सुगम बनाने के लिए आईसीपी और एलसीएस के आधारभूत ढाँचे में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। आधारभूत संरचना की प्रमुख आवश्यकताओं में आधुनिक गोदाम सुविधाओं के साथ भूमि बंदरगाह का विकास, खाद्य परीक्षण सुविधा, आईटी और दूरसंचार सहयोग, वजन मापने हेतु धर्मकाँटा, संपर्क सड़कों और पुलों का विकास शामिल है।

एशियाई क्षेत्र में बाजारों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पूर्वोत्तर: एशियाई क्षेत्र में पड़ोसी बाजारों में प्रवेश करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र एक प्रमुख स्प्रिंगबोर्ड के रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है। नदियों से संपन्न इस क्षेत्र में सड़क, रेल और नदी आधारित परिवहन के बहुपक्षीय मॉडल को लागू करने का भी उचित अवसर है। किसी स्थान पर उपयुक्त आधारभूत ढाँचे और नीतिगत सहयोग के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र, भारत और पड़ोसी देशों तथा अन्य एशियाई देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य की सुविधा प्रदान करने की क्षमता रखता है। लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता के साथ तटीय शिपिंग बांग्लादेश और म्यांमार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों स्थित बंदरगाहों के बीच माल के प्रभावी परिवहन के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

संपर्क तथा संबंधित आधारभूत संरचना के निर्माण की आवश्यकता: यह आवश्यक हो गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर तथा उन्हें आपस में रणनीतिक रूप से जोड़कर सीमा व्यापार केंद्रों से जोड़ा जाए। वर्तमान में निर्माणाधीन केएमटीटीपी, समुद्र के रास्ते म्यांमार के राखीने राज्य में स्थित सितवे बंदरगाह को कोलकाता से जोड़ेगा। इसके बाद, यह म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह को कलादान नदी (नौवहन मार्ग) द्वारा चिन राज्य को पलेटवा से जोड़ेगा, और फिर पलेटवा को सड़क द्वारा मिजोरम से जोड़ेगा। इस प्रकार, म्यांमार में कॉरीडोर को विकसित करने तथा भारतीय महाद्वीप और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के बीच माल परिचालन के लिए समुद्र, नदी और सड़क परिवहन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। माल ढुलाई के नियमित परिचालन को वहन करने के लिए यह आवश्यक है कि सड़कों, विशेष रूप से व्यापार मार्गों की आधारभूत परिवहन संरचना को तत्काल अपग्रेड किया जाए।

सुव्यवस्थित कार्यान्वयन हेतु बैंकिंग सुविधा: भारत और म्यांमार के बीच सीमा व्यापार को सामान्य व्यापार में पूरी तरह परिवर्तित करने में एक बड़ी समस्या यह है कि भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर मुद्रा-विनिमय की कोई मानक सुविधा नहीं है। अत: भारतीय व्यापारियों के लिए आधिकारिक बैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से सीमा पर म्यांमार के साथ व्यापार करना आर्थिक दृष्टि से उपादेय नहीं है। विदेशी मुद्रा लेनदेन और साख पत्र सुविधाओं के प्रबंधन हेतु उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अधिकृत बैंकों की संख्या भी सीमित है। इसके अलावा, भारतीय बैंक बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेशी बैंकों के साथ सीधे लेनदेन नहीं कर सकते। भारत-म्यांमार सीमा पर, बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से व्यापार संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं। इस समस्या से बचने का एक उपाय यह भी हो सकता है कि बैंक के हितधारकों समेत, व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों, राजदूतों तथा उद्योग प्रतिनिधियों को बुलाकर सबके बीच एक कार्यशाला आयोजित की जाए।

बॉर्डर हाट की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता: भारत-म्यांमार के बीच सीमा पार व्यापार के सामान्यीकरण के साथ यह अत्यधिक आवश्यक हो गया है कि सामरिक बिंदुओं पर बॉर्डर हाट की संख्या में तत्काल वृद्धि की जाए तथा उन्हें सशक्त बनाया जाए। भारत-म्यांमार सीमा पर बॉर्डर हाट की स्थापना द्वारा स्थानीय लोगों के बीच आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए सीमा पार नियमित बस सेवाओं हेतु एक मार्ग भी बनाया जा सकता है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में 'मेक इन इंडिया' अभियान: सीमा व्यापार आँकड़े विशेष रूप से मोरे तथा जोखावथर में प्रतिस्थापित भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विनिर्माण केंद्र की स्थापना पर बल देते हैं। जबकि म्यांमार के जोखवथार में स्थित भूमि कस्टम स्टेशन से होने वाला आधिकारिक आयात अधिकतर अरेका अखरोट तक ही सीमित था, कभी-कभी बेंत वाली झाड़ू और काली मिर्च का आयात भी होता था, जबकि आधिकारिक निर्यात आंकड़े में व्यापार की केवल एक ही वस्तु, 'सोयाबीन की बड़ी' होती थी। मोरे सीमा पर विविध निर्यातित वस्तुओं में गेहूं का आटा, ब्लीचिंग पाउडर, सूखी मिर्च और सूखे अंगूर का आयात शामिल है, जबकि एकमात्र आयातित वस्तु अरेका अखरोट है। तथापि यह ज्ञात हुआ है कि अनौपचारिक माध्यम से जोखावथर से म्यांमार को बड़ी मात्रा में अन्य वस्तुओं का निर्यात हुआ है, जिसमें उर्वरक (स्थानीय रूप से लेई ची के रूप में जाना जाता है), दवाएं, मोटरसाइकिल, कीटनाशक, साइकिल पार्ट्स तथा सौर गियर शामिल हैं। वास्तव में, उर्वरकों और दवाइयों से भरे कई ट्रकों के हर हफ्ते म्यांमार भेजे जाने की भी संभावना है। इसी तरह का अवैध व्यापार मोरे सीमा पर भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर भी होता है। अत: यह जरूरी है कि उन वस्तुओं की पहचान की जाए, जिनकी मांग सीमा पार बहुत अधिक है और तदनुसार एक विनिर्माण इकाई स्थापित की जाए, इस तरह भारत सरकार की योजना "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा मिलेगा और रोजगारों के नए द्वार भी खुलेंगे।

पूर्वोत्तर में कार्बनिक कृषि आधारित उद्योगों का संवर्धन: पूर्वोत्तर राज्य निर्यातों के लिए कुछ प्रमुख उद्योगों पर फोकस कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्रमुख उद्योग है जैविक उद्योग, जो इस क्षेत्र को भारत के जैविक केंद्र के रूप में बदल सकता है। मुख्य रूप से जैविक कृषि उत्पादन वाला पूर्वोत्तर भारत के जैविक कृषि निर्यात में वृद्धि में महत्त्वपूर्ण हो सकता है। जैविक खेती के विकास की संभावनाओं को देखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के विकास हेतु वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा ₹100 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। यह पहल पूर्वोत्तर राज्यों को वाणिज्यिक जैविक खेती के विकास से लाभ उठाने और कृषि प्रणाली को जैविक कृषि प्रणाली में परिवर्तित करने के उद्देश्य से की गई है।

4 टेक्निकल टेक्सटाइल

टेक्निकल टेक्सटाइल एक उभरता हुआ उच्च तकनीक क्षेत्र है, जो तेजी से भारत में अपना स्थान बना रहा है। परंपरागत रूप से कपड़े सजावट एवं पहनने से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसके विपरीत टेक्निकल टेक्सटाइल में फाइबर और सामग्रियां शामिल हैं, जिनके विनिर्माण में सौंदर्य के बजाय उनकी उपयोगिता को प्राथमिकता दी जाती है। मोटर वाहन, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, निर्माण परियोजनाएं, खेल, परिवहन, रक्षा विभाग, पोत परिवहन जल शोधन के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें इन उत्पादों का विनिर्माण होता है। उत्पादों के गुणों, उपयोगिता और ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग को 12 क्षेत्रों अर्थात् एग्रोटेक, बिल्डटेक, क्लॉथटेक, जियोटेक, होमटेक, इंदुटेक, मेडिटेक, मोबिलटेक, ओकोटेक, पैकटेक और प्रोटेक में विभाजित किया गया है। भारतीय टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग में वृद्धि एवं विकास की अच्छी क्षमता है। वैश्विक टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग का लगभग 3% भाग का उत्पादन भारत में किया जाता है, जो कि लगभग 90,000 मीट्रिक टन आंका गया है। कपास, मानव निर्मित फाइबर, रेशम, ऊन और जूट जैसे कच्चे माल (फाइबर) की उपलब्धता की दृष्टि से भारत इस क्षेत्र में अद्वितीय है। उच्च विकास दर प्राप्त करने के बावजूद, भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल की प्रति व्यक्ति खपत विकसित देशों में 10-12 किलोग्राम के मुकाबले 1.7 रुपये प्रति किलो है। यूरोप और चीन को वैश्विक बाजार में वस्त्रों के इस क्षेत्र के प्रमुख निर्माताओं और निर्यातकों के रूप में देखा जाता है। वैश्विक आयात के संदर्भ में देखें तो अमेरिका और यूरोप वैश्विक क्षेत्र में अग्रणी हैं। वहीं, वैश्विक टेक्निकल टेक्सटाइल निर्यात में लगभग 4 प्रतिशत और वैश्विक आयात में लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा भारत का है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान भारत के घरेलू बाजार का व्यापार मूल्य 9.9% की सीएजीआर से बढ़ते हुए, वर्ष 2017-18 में ₹1,16,217 करोड़ रुपए हो गया। अनुमान है कि वर्ष 2020-21 तक इस उद्योग का मूल्य ₹2,00,823 करोड़ हो जाएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल बाजार में, वर्ष 2017-18 में 41.6% के साथ अधिकांश हिस्सा पैकटेक उत्पादों का रहा। इसके बाद क्रमश: इंदुटेक (11.3%), होमटेक (10.5%) और मोबिलटेक (9.8%) का स्थान रहा।

व्यापार

टेक्निकल टेक्सटाइल एक उभरता हुआ उच्च तकनीक क्षेत्र है तथा भारत में इसके विकास की काफी संभावनाएं हैं। भारत टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पादों का निर्यातक है और वर्ष 2017-18 के दौरान इनका निर्यात 1.85 अरब यूएस डॉलर का रहा। वर्ष 2013-14 से 2017-18 अर्थात पाँच वर्षों के दौरान भारतीय निर्यातों में 3.3% की सीएजीआर दर्ज की गई। अमेरिका, भारत द्वारा निर्यातित टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पादों का अग्रणी आयातक है तथा वर्ष 2017-18 में इसका अनुमानित निर्यात मूल्य 336.8 मिलियन यूएस डॉलर रहा। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान अमेरिका को निर्यातित मूल्य में 10.6% की सीएजीआर दर्ज की गई तथा कुल निर्यात में इसकी भागीदारी 13.9% से बढ़कर 18.2% हो गई। इसी अवधि के दौरान चीन टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा। इसके बाद जर्मनी और ब्रिटेन का स्थान रहा। भारत से निर्यातित टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पादों के अन्य प्रमुख आयातकों में स्पेन, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, फ्रांस और बेल्जियम शामिल हैं। पैकटेक उत्पाद 43.2% हिस्सेदारी के साथ भारत के टेक्निकल टेक्सटाइल बाजार पर प्रभाव बनाए हुए है, इसके बाद इंदुटेक उत्पाद (32%), होमटेक (11.6%) और मेडिटेक (5.8%) का स्थान है।

सरकारी योजनाएं

टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विभिन्न सहयोगी योजनाएं शुरू की हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए शुरू की गई इन महत्त्वपूर्ण योजनाओं में एक योजना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन रहा है, जिसे पांच वर्ष (वर्ष 2010-11 से 2014-15) के लिए लागू किया गया था तथा बाद में वर्ष 2017 तक बढ़ा दिया गया। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य मुख्य रूप से मानकीकरण, कॉमन परीक्षण सुविधाओं के निर्माण और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना तथा दूसरा उद्देश्य इस क्षेत्र के नव उद्यमों और अनुसंधान क्षेत्र में सहायता प्रदान कर टेक्निकल टेक्सटाइल के घरेलू तथा निर्यात बाजार के विकास में सहयोग करना है।

संभावनाएँ

हालांकि भारत वर्तमान में टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पादों का निवल निर्यातक है, लेकिन इन उत्पादों की घरेलू मांग भी तेजी से बढ़ रही है, अत: यह आवश्यक हो गया है कि घरेलू उत्पादन की क्षमता में भी वृद्धि की जाए। टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में उत्पन्न ये नए अवसर, केवल इन उत्पादों की बढ़ती घरेलू मांग के कारण ही नहीं हैं, बल्कि अमेरिका जैसे पारंपरिक बाजारों तथा चीन, जापान, कोरिया और ताइवान जैसे नए बाजारों में बढ़ती मांग के कारण भी उभर रहे हैं। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कुछ उपायों पर बल देना आवश्यक है, जैसे- विशिष्ट उद्योगों में नियामक मानदंड स्थापित कर टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि इससे इनकी खपत में वृद्धि हो, उत्पादन गुणवत्ता में सुधार आए, संचालन मानकों में सुधार तथा अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए।

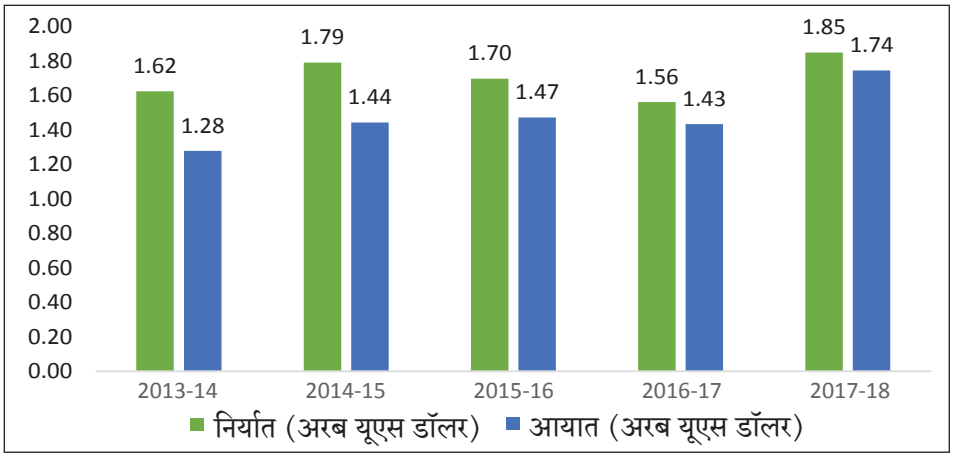

स्रोत: डीजीआईसीएसएस; एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

द्विपक्षीय व्यापार

पिछले दशक में चीन के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार में दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई। व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका को प्रतिस्थापित करते हुए वर्ष 2000-01 से चीन, भारत का सबसे बड़ा भागीदार बन गया है, जो भारत से होने वाले कुल आयातों में 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। वर्ष 2008-09 में, चीन के साथ भारत का व्यापार 41.9 अरब यूएस डॉलर रहा, जिसमें भारत द्वारा 9.4 अरब यूएस डॉलर का निर्यात और 32.5 अरब यूएस डॉलर का आयात किया गया और इस तरह 25.1 अरब यूएस डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया गया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह व्यापार घाटा वर्ष 2017-18 तक 62.9 अरब यूएस डॉलर तक पहुंच गया। पिछले दशक के दौरान चीन से भारत के आयात 9.9 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़े, जबकि इसकी तुलना में निर्यात में केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में 13.3 अरब यूएस डॉलर के व्यापार के साथ चीन, भारत का चौथा सबसे बड़ा आयातक रहा, जबकि वर्ष 2008-09 में भारतीय निर्यातों में चीन की भागीदारी 5 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई थी। दूसरी ओर, पिछले दशक में भारत के आयातों में चीन की हिस्सेदारी 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 16.4 प्रतिशत हो गई।

वर्ष 2017-18 के दौरान भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जैविक रसायन (15.8 प्रतिशत), तांबा तथा सामग्री (11.6 प्रतिशत), खनिज ईंधन, तेल एवं उनके आसवन (11.3 प्रतिशत), अयस्क, धातुमल तथा स्लैश (9.4 प्रतिशत) और कपास (7.5 प्रतिशत) थे, जो मुख्य रूप से प्राथमिक निर्यात वस्तु हैं। चीन से भारत को आयातित वस्तुओं में मुख्य रूप से उच्च तकनीक वाले उत्पाद शामिल हैं, जैसे- विद्युत मशीनरी और उपकरण (37.6 प्रतिशत), मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (17.8 प्रतिशत), कार्बनिक रसायन (9.3 प्रतिशत), प्लास्टिक और प्लास्टिक की वस्तुएँ (3.1 प्रतिशत) और ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक तथा चिकित्सा उपकरण (2.2 प्रतिशत) इत्यादि।

द्विपक्षीय निवेश

अप्रैल 1996 से मार्च 2018 के दौरान चीन में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक

चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार

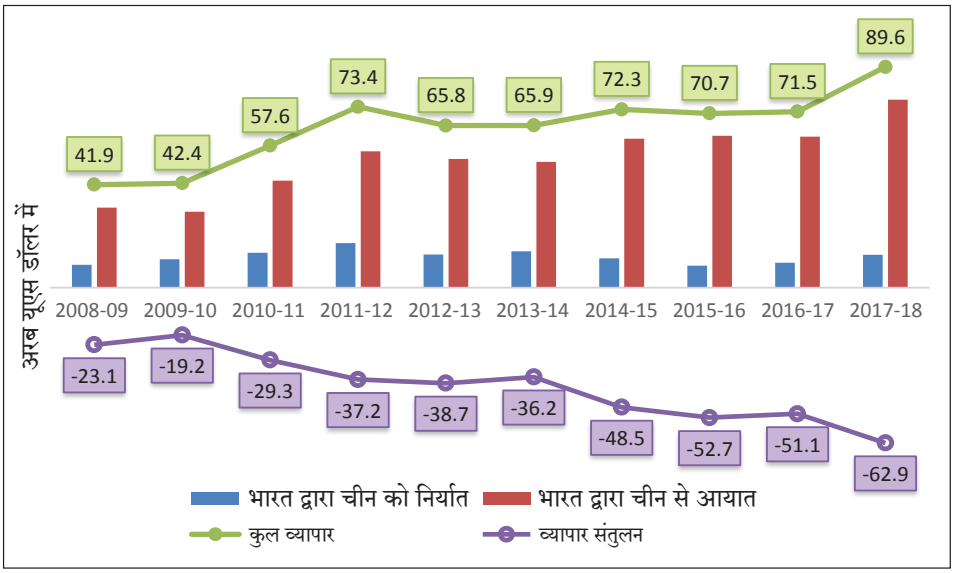

स्रोत : उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार; एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

कंपनियों में अनुमोदित भारतीय संचयी एफडीआई 1.5 अरब यूएस डॉलर का रहा। भारतीय कंपनियों ने मुख्य रूप से विनिर्माण (दवाइयों, रीफ्रैक्ट्री, लेमिनेटेड ट्यूब, ऑटो पुर्जे, पवन ऊर्जा इत्यादि), सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं (आईटी शिक्षा, सॉफ्टवेयर समाधान, और विशिष्ट सॉफ्टवेयर उत्पादों सहित), व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र में निवेश किया। चीन में व्यापार करने वाली प्रमुख भारतीय कंपनियों में रैनबैक्सी, ऑर्किड फार्मास्युटिकल्स, डॉ रेड्डी लैबोरेटरीज़, अरबिंदो फार्मा, नीट (एनआईआईटी), भारत फोर्ज, इंफोसिस, टीसीएस, सत्यम कंप्यूटर्स, ऐपटेक, ओरिंड रीफ्रेक्ट्रीज, एसेल पैकेजिंग, सुजलॉन एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, केजीके डायमंड्स, सुंदरम फास्टनर्स, बिनानी सीमेंट इत्यादि शामिल हैं।

अप्रैल 2000 से मार्च 2018 के दौरान, चीन से भारत में संचयी एफडीआई प्रवाह 2 अरब यूएस डॉलर (भारत के कुल एफडीआई प्रवाह का 0.5%) रहा। चीन में व्यापार करने वाले भारतीय बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। भारत में मौजूद कुछ चीनी कंपनियों में, साइनोस्टील, शौगांग इंटरनेशनल, बाओशन आयरन एंड स्टील लिमिटेड, सैनी हेवी इंडस्ट्री लिमिटेड, चोंगकिंग लाइफैन इंडस्ट्री लिमिटेड, चाइना डोंगफैंग इंटरनेशनल और चाइना हाइड्रो कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी कंपनियां शामिल हैं। भारत में ह्युवेई टेक्नोलॉजीज, जेडटीई, टीसीएल, हायर और बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, निजी क्षेत्र की चीनी कंपनियां हैं।

अन्य क्षेत्रों के माध्यम से सहयोग

दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को संयुक्त आर्थिक समूह, रणनीतिक आर्थिक वार्ता, नीति आयोग और विकास अनुसंधान केंद्र वार्ता और वित्तीय वार्ता जैसे विभिन्न वार्ता तंत्रों के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। दोनों देशों के बीच कुछ अन्य संस्थागत वार्ता तंत्रों में व्यापार पर संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी), कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग पर जेडब्ल्यूजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और उच्च प्रौद्योगिकी पर जेडब्ल्यूजी, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) पर संयुक्त अध्ययन समूह और संयुक्त कार्य बल, कृषि पर भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी समूह, ऊर्जा-सहयोग पर भारत-चीन संयुक्त कार्य समूह और बीसीआईएम आर्थिक कॉरीडोर पर संयुक्त अध्ययन समूह शामिल हैं।

6 लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई क्षेत्र में निवेश

लैटिन लगभग 637.7 मिलियन की आबादी वाले लैटिन अमेरिका तथा कैरीबियाई (लैक) क्षेत्र की संयुक्त जीडीपी 4.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रगति की है। क्षेत्र की जीडीपी प्रति व्यक्ति (पीपीपी नियमानुसार) वर्ष 1980 में 4,565 यूएस डॉलर से तीन गुना बढ़कर वर्ष 2017 में 15,649 यूएस डॉलर हो गई। इस क्षेत्र में युवा, शिक्षित और कुशल श्रमशक्ति है। औद्योगिक और विनिर्माण मजबूती तथा व्यापार सुगमता मानकों में होते लगातार सुधार के चलते इसे निवेश के लिए एक महत्वूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। कृषि के साथ-साथ यहां तेल, चांदी, सोने, तांबे, कोयले, बॉक्साइट, लिथियम और निकेल जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं।

लैक क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह वर्ष 2007 के 117 अरब यूएस डॉलर से 29% बढ़कर वर्ष 2017 में 151 अरब यूएस डॉलर तक पहुंच गया तथा वर्ष 2018 में इसके 140 अरब यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में कमी, वस्तुओं की घटती कीमतों और उच्च विनिमय दर में अस्थिरता आ जाने के कारण एफडीआई प्रवाह में कमी आई है। वर्ष 2007 से 2017 के दौरान लैक क्षेत्र में 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का संचयी निवेश हुआ है, अत: वैश्विक निवेश प्रवाह के लिए यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। पूंजी इनफ्लो के संबंध में, वर्ष 2017 में लैक क्षेत्र में मेक्सिको में सबसे अधिक निवेश किया गया। वर्ष के दौरान कुल पूंजी निवेश का लगभग 40% हिस्सा मेक्सिको में ही निवेश किया गया। इसके बाद ब्राजील का स्थान रहा, जिसका कुल पूंजीगत निवेश में 15% हिस्सा रहा। लैक में पेरू (7%), उरुग्वे (6%), और चिली (6%) अन्य प्रमुख पूंजी निवेश प्राप्तकर्ता देश रहे।

लैक क्षेत्र में सबसे बड़े निवेश को आकर्षित करने वाले उद्योगों को देखा जाए, तो कुल पूंजी निवेश प्रवाह में 14.4% हिस्सेदारी के साथ संचार क्षेत्र अव्वल रहा। इसके बाद वैकल्पिक और अक्षय ऊर्जा (12.2%), धातु (9.6%), कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस (6.9%), और कागज, मुद्रण और पैकेजिंग (6.7%) का स्थान रहा।

वर्ष 2007 से 2017 के दौरान, अमेरिका लैक क्षेत्र में संचयी निवेश के सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा। अमेरिका द्वारा कुल एफडीआई 239.3 अरब यूएस डॉलर रहा, जो लैक क्षेत्र में कुल एफडीआई प्रवाह के पांचवें हिस्से से कुछ अधिक है। अमेरिका के बाद स्पेन (121.1 अरब यूएस डॉलरका एफडीआई) और जर्मनी (64.5 अरब यूएस डॉलर का एफडीआई) का स्थान रहा। एशियाई देशों के विकसित देश- जैसे चीन, शीर्ष 10 निवेशकों पर हावी हैं, जो अब 46.7 अरब यूएस डॉलर के संचयी निवेश और 4% की हिस्सेदारी के साथ क्षेत्र में 9वें सबसे बड़े निवेशक हैं, और अब भारत 8.4 अरब यूएस डॉलर के संचयी निवेश और 1% की भागीदारी के साथ इस क्षेत्र में 22 वां सबसे बड़ा निवेशक है।

लैक क्षेत्र में भारतीय निवेश

लैक के साथ भारत की भागीदारी समय के साथ बढ़ रही है। अप्रैल 1996 से मार्च 2011 के दौरान, लैक क्षेत्र को भारत की बहिर्गमन एफडीआई (ओएफडीआई), संचित रूप से 6.3 अरब यूएस डॉलर रहा, जो इस अवधि के दौरान भारत से उत्पन्न कुल ओडीआई का 4.7% था। ब्रिटेन वर्जिन द्वीप तथा केमैन द्वीप (भारतीय एफ़डीआई निवेश हेतु प्रमुख गंतव्य स्थान) को जमा की जाने वाली ओएफडीआई में प्रमुख रूप से घाटा दर्शाते हुए भारतीय ओएफडीआई वर्ष 2011-12 में 3.8 अरब यूएस डॉलर से 21% की बढ़ोतरी करते हुए वर्ष 2013-14 में 4.6 अरब यूएस डॉलर तक पहुंचने के बाद वर्ष 2017-18 (आंकड़ा-1) में गिरकर यह 622.1 मिलियन यूएस डॉलर रह गया।

अप्रैल 2011 से नवंबर 2017 के दौरान, लैक क्षेत्र में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप भारतीय ओएफडीआई सबसे बड़ा गंतव्य था, जिसमें भारतीय निवेश का 45.9% हिस्सा था, इसके बाद केमैन द्वीप (32.9%), पनामा (13.8%), बरमूडा (3.4%) , और ब्राजील (1.5%) का नाम आता है।

संचार, मोटर वाहन, वैकल्पिक / अक्षय ऊर्जा, धातु, व्यापार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, भोजन और तंबाकू और हाइड्रोकार्बन, इत्यादि भारतीय निवेशकों के लिए लैक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने हेतु अवसर प्रदान करते हैं।

आंकड़ा1 : ओएफ़डीआई को भारत का लैक

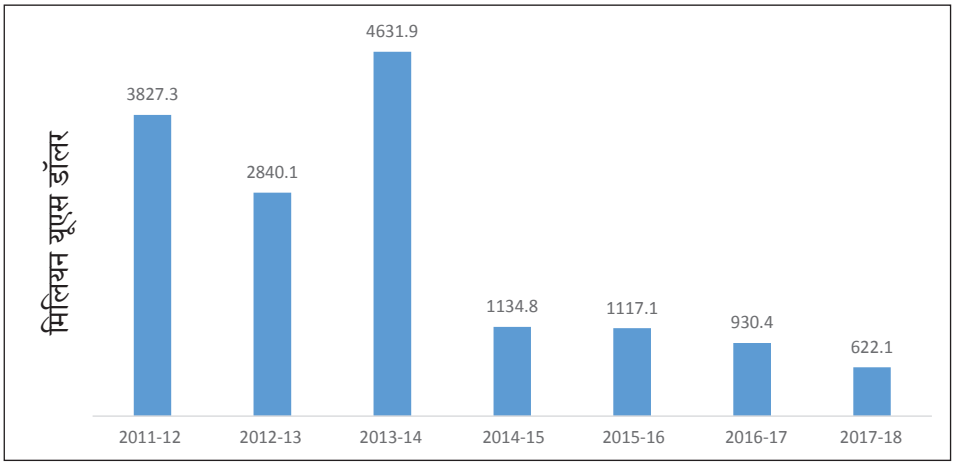

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक; एक्ज़िम बैंक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

भारत का इस्पात उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस्पात क्षेत्र का 2% से अधिक योगदान है। विश्व इस्पात संघ के मुताबिक, वर्ष 2017 में वैश्विक कच्चे इस्पात का उत्पादन 1689 मीट्रिक टन दर्ज किया गया था तथा वैश्विक कच्चे इस्पात का लगभग 50% उत्पादन चीन द्वारा किया गया। भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसने वर्ष 2017 में वैश्विक कच्चे इस्पात का लगभग 6% उत्पादन किया।

भारतीय परिदृश्य

भारतीय इस्पात उद्योग ने कच्चे इस्पात के उत्पादन क्षेत्र में पहली बार 100 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर रिकॉर्ड कायम है। वर्ष 2017-18 में, पिछले वर्ष की तुलना में 4.5% की वृद्धि दर्ज करते हुए कच्चे इस्पात का उत्पादन 102.3 मीट्रिक टन रहा। वर्ष के दौरान 76% उपयोग दर की क्षमता के साथ भारत की कच्चे इस्पात उत्पादन क्षमता में 5% की वृद्धि हुई और यह 134.6 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। जबकि भारतीय बाजार में शीर्ष 6 इस्पात उत्पादकों ने वर्ष 2016-17 से 6.1% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2017-18 में 59.4 मीट्रिक टन का उत्पादन किया। इसी दौरान वर्ष 2017-18, में अन्य उत्पादकों ने 1.1% की निम्न वृद्धि दर्ज करते हुए 42.9 मीट्रिक टन का उत्पादन किया। वर्ष 2017-18 के दौरान, बिक्री के लिए उत्पादन 104.9 मीट्रिक टन रहा, जिसमें 2016-17 की तुलना में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें गैर-मिश्र धातु इस्पात खंड का योगदान 94.8 मीट्रिक टन रहा और शेष मिश्र धातु इस्पात खंड में 20.7% की महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज कई गई। कुल तैयार इस्पात की खपत वर्ष 2016-17 की तुलना में 7.9% की वृद्धि करते हुए वर्ष 2017-18 में, 90.7 मीट्रिक टन रही।

व्यापार

इस्पात क्षेत्र में भारत का कुल व्यापार वर्ष 2013-14 के 11.5 मीट्रिक टन से 10.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2017-18 में 17.0 मीट्रिक टन हो गया। भारतीय आयात में जिस समय 14.8% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की जा रही थी, उसी समय भारतीय निर्यात में 20.9% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2017-18 में 2.2 मीट्रिक टन अधिशेष तक पहुंचने से पहले इस्पात व्यापार में वर्ष 2015-16 में (-) 7.6 टन का व्यापार घाटा दर्ज किया गया था।

अमेरिका द्वारा लागू टैरिफ का प्रभाव

23 मार्च, 2018 से, अमेरिका ने दो वस्तुओं के आयात पर छूट देने की शुरुआत की। इस्पात की कुछ वस्तुओं पर 25% टैरिफ और एल्यूमीनियम की कुछ वस्तुओं पर 10% टैरिफ। हालांकि भारत दोनों ही धातुओं का प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता है, लेकिन भारत पर इसका प्रभाव देखा जाए तो निर्यात बाजार में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी कोई अहम हिस्सेदारी नहीं है। उदाहरणार्थ, अमेरिका द्वारा आयातित वस्तुओं में भारत की हिस्सेदारी, इस्पात वस्तुओं के आयात में केवल 1.6% और एल्यूमीनियम वस्तुओं के आयात में केवल 2.2% है। अत: संभव है कि अमेरिका द्वारा लागू टैरिफ का प्रभाव भारत पर कम हो।

तथापि, वर्ष 2017 में भारत के इस्पात वस्तुओं के निर्यात में अमेरिकी शेयर 18.1% दर्ज किया गया तथा यह भारत से निर्यातित वस्तुओं का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा। वर्ष 2013, 2014 और 2015 में, अमेरिका इन वस्तुओं का प्रमुख आयातक रहा। इसी प्रकार, भारत के एल्यूमीनियम वस्तुओं का भी अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा, जिसने 2017 में कुल एल्यूमीनियम वस्तुओं का 13.5% आयात किया।

संभावनाएं

घरेलू इस्पात उद्योग को खराब आयात से बचाने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में कुछ इस्पात उत्पादों पर सुरक्षा शुल्क लागू कर दिया था (जिसे बाद में मार्च 2018 तक बढ़ा दिया गया)। उसी समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग के निर्माण हेतु राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 को मंजूरी दी। एनएसपी 2017 में वर्ष 2030 तक स्टील निर्माण क्षमता को 300 मिलियन टन (एमटी) तक बढ़ाने तथा 160 किलो प्रति व्यक्ति स्टील खपत का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, कई सरकारी योजनाओं द्वारा किफायती आवास उपलब्ध कराने, रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने, घरेलू जहाज निर्माण उद्योग के विकास, निजी भागीदारी हेतु रक्षा क्षेत्र खोलने जैसी पहलें की गई हैं साथ ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अनुमानित विकास के आधार पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि इन सबके चलते इस्पात उद्योग की मांग में भारी वृद्धि हो सकती है। हालांकि, यह उद्योग अनर्जक आस्तियों की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन विभिन्न साधनों के माध्यम से बकाया राशि के निपटारे के बाद समेकन की भी पर्याप्त संभावना है। इससे क्षमता के बेहतर उपयोग, तालमेल सुधार और उत्पादन लागत घटने की उम्मीद है।

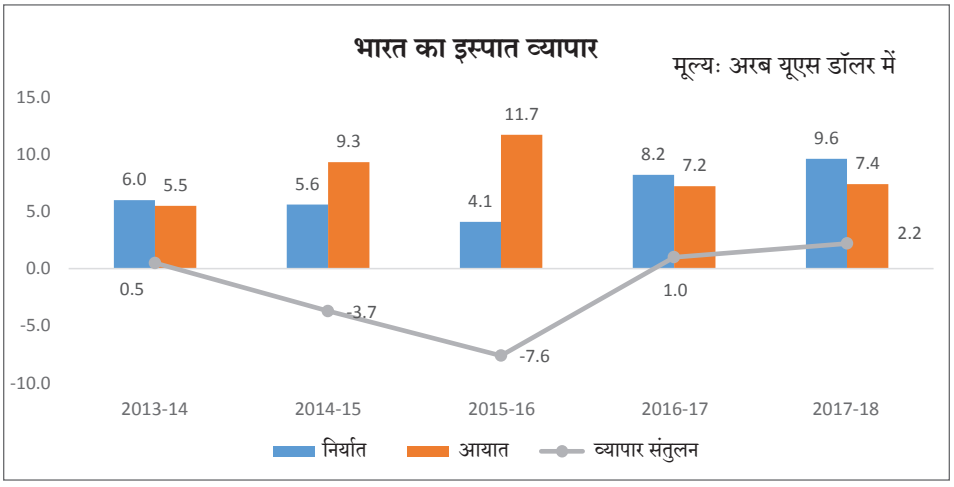

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

8 भारत–श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध

पूर्व औपनिवेशिक काल से ही भारत और श्रीलंका सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंधों की विरासत से जुड़े हुए हैं। विकास, शिक्षा, संस्कृति और रक्षा क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों में समय के साथ घनिष्ठता आई है। इसकी भौगोलिक निकटता, हिंद महासागर में रणनीतिक स्थान तथा प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए, भारत के व्यापार और निवेश के लिए श्रीलंका प्राथमिक स्थानों में से एक रहा है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में उदारीकरण के साथ 1990 के दशक के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक संबंध भी बढ़े हैं। नतीजतन, पिछले एक दशक में, श्रीलंका में भारत का निर्यात वर्ष 2008 के 2.8 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 3.1 अरब यूएस डॉलर हो गया। इसी प्रकार श्रीलंका से भारत का आयात भी वर्ष 2008 के 0.5 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 0.6 अरब यूएस डॉलर हो गया। भारत ने पिछले कुछ वर्षों से श्रीलंका के साथ व्यापार संतुलन बनाए रखा है, वर्ष 2008 के 2.3 अरब यूएस डॉलर (चार्ट) से बढ़कर वर्ष 2017 में 2.6 अरब यूएस डॉलर तक पहुंच गया।

वर्ष 2017 के दौरान भारत द्वारा श्रीलंका को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद का नाम सबसे पहले आता है, जिसका श्रीलंका को भारत द्वारा कुल निर्यात का 16.6 प्रतिशत भाग है, इसके बाद परिवहन वाहन (12.5 प्रतिशत), लौह और इस्पात (6.7 प्रतिशत), अनाज (5.2 प्रतिशत), जहाज, नाव एवं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर (4.9 प्रतिशत), और कपास (4.9 प्रतिशत) इत्यादि शामिल हैं।

वर्ष 2017 में श्रीलंका से आयातित प्रमुख वस्तुओं में कॉफी, चाय और मसाले शामिल रहे, जिनका हिस्सा श्रीलंका से भारत द्वारा कुल आयात का 16.5 प्रतिशत रहा। इसके बाद विमान, अंतरिक्ष यान और उनके पुर्जे (10.9 प्रतिशत), खाद्य उद्योग एवं पशु चारे के अवशिष्ट (8 प्रतिशत), खाद्य फल और अखरोट (7.4 प्रतिशत), लकड़ी की लुगदी (4.8 प्रतिशत) और विद्युत मशीनरी और उपकरण (4 प्रतिशत) शामिल रहे।

भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय निवेश

भारत और श्रीलंका में 22 जनवरी 1997 को द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार (बीआईपीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 13 फरवरी, 1998 से लागू हुआ। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 1996 से मार्च 2018 के दौरान श्रीलंका में भारत द्वारा अनुमोदित संचयी निवेश 1.5 अरब यूएस डॉलर का रहा।

एफडीआई मार्केट्स डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2007 से 2016 के दौरान भारत ने श्रीलंका में 61 एफडीआई परियोजनाओं में 5.3 अरब यूएस डॉलर का निवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप 14,196 नौकरियां सृजित हुईं। अत: भारत, श्रीलंका में सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा। श्रीलंका में इस अवधि के दौरान किए गए कुल निवेश का यह 30.7 प्रतिशत हिस्सा है। इस अवधि के दौरान कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा यानी 1.9 अरब यूएस डॉलर निवेश किया गया, इसके बाद रियल एस्टेट (1.2 अरब यूएस डॉलर), वित्तीय सेवाएं (0.6 अरब यूएस डॉलर), होटल और पर्यटन (0.5 अरब यूएस डॉलर) और ऑटोमोटिव ओईएम (0.2 अरब यूएस डॉलर) स्थान रहा। श्रीलंका में निवेश करने वाली कुछ प्रमुख भारतीय कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), एनटीपीसी लिमिटेड (नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड), महिंद्रा एंड महिंद्रा (एम एंड एम), आईटीसी, भारती एयरटेल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एलआईसी), एमआरएफ लंका, टीवीएस ग्रुप, अंबुजा सीमेंट इत्यादि शामिल हैं। श्रीलंका में मौजूद कुछ प्रमुख भारतीय बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी), इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं। लंका एलआईसी, एलआईसी ऑफ इंडिया की ही अनुषंगी कंपनी है, जो श्रीलंका में भी बीमा क्षेत्र में संचालित है।

इसी तरह, श्रीलंका ने वर्ष 2007 से 2016 के दौरान भारत में 15 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में 0.6 अरब यूएस डॉलर पूंजी निवेश की है। श्रीलंका ने परिवहन (360.6 मिलियन यूएस डॉलर), वित्तीय सेवाएं, वस्त्र तथा भोजन एवं तंबाकू जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश किया है। भारत में निवेश करने वाली श्रीलंकाई कंपनियों में सीएल सिनर्जी, बैंक ऑफ सिलोन, फैशन 365 रिटेल, एपेक्सौरा, कंदुरता अम्ब्रैला इंडस्ट्री तथा ओडल इत्यादि शामिल हैं। बैंक ऑफ सेलोन भारत में कार्यरत बैंक है तथा इसकी सेवाएं केवल वाणिज्यिक संचालन और कैटरिंग तक ही सीमित हैं तथा इसमें श्रीलंकाई लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

चार्ट: श्रीलंका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार (अरब यूएस डॉलर)

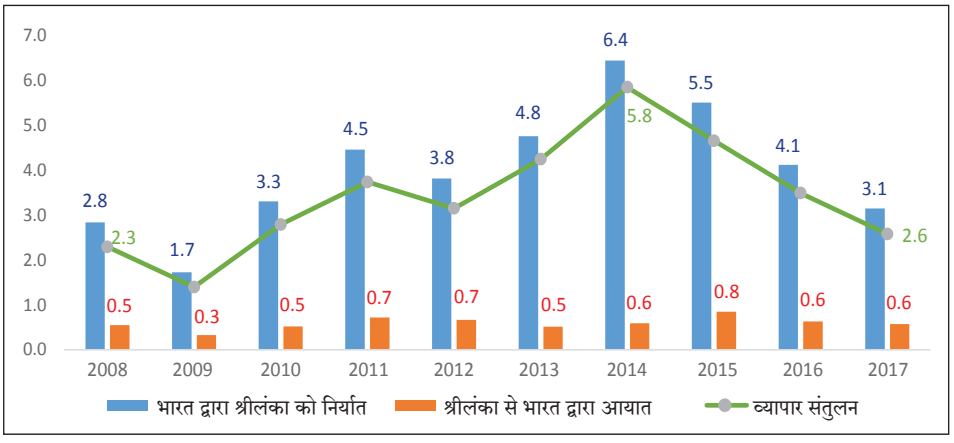

स्रोत: आईटीसी ट्रेडमैप

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मध्यम उद्यमों पर विशेष बल के साथ भावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है। ये ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातक समुदाय को जोखिम और दायित्व रहित निर्यात वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करती हैं, जो उन्हें नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने और मौजूदा विदेशी बाजारों में निर्यात बढ़ाने में मदद करती हैं। एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और सीआईएस क्षेत्रों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। बैंक द्वारा अब तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 22.79 अरब यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 234 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्द्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं। एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से अप्रैल-जून, 2018 की अवधि के दौरान निम्नलिखित छह ऋण-व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए:

(i) रवांडा सरकार को बेस-बुटारो-किडाहो रोड परियोजना के लिए 66.6 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। उक्त ऋण-व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा रवांडा सरकार को भारत सरकार की ओर से अब तक 347.65 मिलियन यूएस डॉलर की पांच ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। रवांडा सरकार को इससे पहले प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाएं न्याबोरंगो जलविद्युत परियोजना, निर्यात लक्षित आधुनिक सिंचाई परियोजना तथा 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और बिजनेस इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना के वित्तपोषण के लिए थीं।

(ii) तंजानिया सरकार को तंजानिया के 17 शहरों में जलापूर्ति योजना के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। उक्त ऋण-व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा तंजानिया सरकार को भारत सरकार की ओर से अब तक 1.12 अरब यूएस डॉलर की छह ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। तंजानिया सरकार को इससे पहले प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाएं ट्रैक्टरों की आपूर्ति, पंपों एवं उपकरणों, वाहनों की खरीद, लेक विक्टोरिया पाइपलाइन के टबोरा, गुंगा एवं ज़ेगा तक विस्तार, जंजीबार में जलापूर्ति के पुनरुद्धार एवं सुधार तथा दार-अस-सलाम में जलापूर्ति परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए थीं।

(iii) क्यूबा सरकार को 51 मेगावाट के पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना और 50 मेगावाट के को-जेनरेशन बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए क्रमशः 70 मिलियन यूएस डॉलर और 90.3 मिलियन यूएस डॉलर की दो ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गईं। उक्त ऋण-व्यवस्थाओं सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा क्यूबा सरकार को भारत सरकार की ओर से अब तक 173.06 मिलियन यूएस डॉलर की पांच ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। क्यूबा सरकार को इससे पहले प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाएं दूध पाउडर प्रसंस्करण, बल्क ब्लेंडिंग उर्वरक संयंत्र और क्यूबा में इंजेक्टेबल उत्पादों के आधुनिकीकरण के लिए संयंत्र की स्थापना के वित्तपोषण के लिए थीं।

(iv) सूरीनाम सरकार को 3 चेतक हेलिकॉप्टरों की सर्विसिंग और रखरखाव तथा ट्रांसमिशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन और बिजली उत्पादन के लिए क्रमशः 3.5 मिलियन यूएस डॉलर और 27.5 मिलियन यूएस डॉलर की दो ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गईं। उक्त ऋण-व्यवस्थाओं सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा सूरीनाम सरकार को भारत सरकार की ओर से अब तक 78.05 मिलियन यूएस डॉलर की सात ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। सूरीनाम सरकार को इससे पहले प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाएं जल आपूर्ति परियोजना, क्रैश फायर टेंडरों की आपूर्ति और सूरीनाम में हेलिकॉप्टरों की खरीद के वित्तपोषण के लिए थीं।

सफलता की कहानी: मोजाम्बिक

एक्ज़िम बैंक ने मोजाम्बिक सरकार को ग्रामीण पेयजल विकास परियोजना के लिए 19.72 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की। इस परियोजना के जरिए मोज़ाम्बिक के विभिन्न प्रांतों के ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति 30% से 50% तक बढ़ी है। परियोजना से 8,24,500 लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सका है। इससे स्थानीय लोगों में हैजा, उल्टी-दस्त जैसी बीमारियों से राहत मिली है और स्वास्थ्य तथा हाईजीन में सुधार आया है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

श्री नदीम पंजेतन,
मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
तल मंज़िल, स्टेट्समैन हाउस,
148 बाराखंबा रोड,
नई दिल्ली - 110001
टेलीफोनः (011) 23474851
फैक्सः (011) 23322758
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

एक्ज़िम बैंक का अध्ययनः पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं में व्यापारः परिदृश्य

एक्ज़िम बैंक द्वारा हाल ही में पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं में व्यापारः परिदृश्य शीर्षक से एक शोध अध्ययन प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में उन वस्तुओं के व्यापार पैटर्न का विश्लेषण किया गया है, जिन्हें देशों के विभिन्न समूहों द्वारा पर्यावरणीय वस्तुओं के रूप में चिह्नित किया गया है। इस अध्ययन में दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, 2001 के बाद से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की व्यापार व पर्यावरण विशेष अधिवेशन समिति (सीटीईएसएस) में पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से संबंधित हुई विभिन्न चर्चाओं का ब्यौरा टाइमलाइन सहित दिया गया है। अध्ययन में संयुक्त राष्ट्र और चीन (सूची दृष्टिकोण); भारत और अर्जेंटीना (पर्यावरण परियोजना दृष्टिकोण और समेकित दृष्टिकोण) और ब्राज़ील (अनुरोध और प्रस्ताव दृष्टिकोण) सहित विभिन्न देशों द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई है।

अध्ययन में देखा गया है कि एपेक सदस्यों (एपेक सूची) में हुई सहमति के अनुसार पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं के निर्यात में भारत का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहा है। 2015 के दौरान भारत के कुल निर्यात का आधे से ज्यादा 3.1 अरब यूएस डॉलर का निर्यात अक्षय ऊर्जा संयंत्र और ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट तथा रिसाइकलिंग प्रणालियों के प्रबंधन जैसी पर्यावरण अनुकूल श्रेणियों में रहा।

व्यापार वित्त पर एक्ज़िम बैंक की संकल्पना को चोगम के दौरान मिली मंजूरी

एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रस्तुत एक विचार को लंदन में हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम) के दौरान औपचारिक रूप प्रदान किया गया। एक्ज़िम बैंक की संकल्पना 'छोटे राष्ट्रमंडलीय देशों को व्यापार वित्त सुविधा' (सीएसएसटीएफएफ) पर चोगम-2018 के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सुविधा के माध्यम से मुख्यतः आयातों पर निर्भर रहने वाले राष्ट्रमंडल के देशों को छोटी अवधि के ऋण (व्यापार वित्त) की उपलब्धता बढ़ाई जा सकेगी। 53 राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में से 31 छोटे द्वीपीय देश हैं, जो मुख्यतः कैरिबियाई और प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं। ये द्वीपीय देश अपने आप में बहुत सक्षम अर्थव्यवस्थाएं नहीं हैं और इन्हें उपभोग की वस्तुओं सहित ज्यादातर चीजें आयात करनी पड़ती हैं। वित्तीय संकट के बाद से विशेष रूप से विकासशील देशों के छोटे बैंकों पर बढ़े हुए जोखिम, और पूंजीगत अपेक्षाओं पर बासेल विनियमों के चलते व्यापार वित्त प्रभावित हुआ है। इस सुविधा का उद्देश्य इन छोटे द्वीपीय देशों को व्यापार प्रवाह अबाधित रूप से जारी रखने के लिए व्यापार वित्त अवरोधों को दूर करना है।

एक्ज़िम बैंक को राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन द्वारा इस प्रकार की सुविधा की व्यवहार्यता पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। एक्ज़िम बैंक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा एक्ज़िम बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम-वाशिंगटन और सेंट्रल बैंक ऑफ माल्टा (सुविधा माल्टा में स्थापित होनी थी) का एक कार्यकारी समूह गठित किया गया।

एक्ज़िम बैंक का शोध अध्ययनः 'सीएलएमवी देशों के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत की प्रतिभागिता बढ़ाना'

कंबोडिया में 21 मई, 2018 को आयोजित पांचवीं भारत-सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में माननीय वाणिज्य एवं

उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु तथा कंबोडिया के माननीय उप प्रधानमंत्री श्री एचओआर नैमहोंग द्वारा भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) के प्रकाशन 'सीएलएमवी देशों के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत की प्रतिभागिता बढ़ाना' का विमोचन किया गया। एक्ज़िम बैंक के अध्ययन में सीएलएमवी देशों के मौजूदा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का विश्लेषण करते हुए इस क्षेत्र के विकास में आने वाली चुनौतियों तथा इन देशों की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में सुधार के लिए रणनीतियां भी सुझाई गई हैं। अध्ययन में बताया गया है कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है। सीएलएमवी क्षेत्र हाल के वर्षों में ऐसे संक्रमण काल से गुजरा है, जहां इन देशों के बदलते स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र परिदृश्य में इलाज के लिए विशेषज्ञ अस्पतालों की जरूरत है। वियतनाम के अलावा इस क्षेत्र के अन्य सभी देशों में बीमा कवरेज न्यून है।

एक्ज़िम बैंक के शोध अध्ययन 'मध्य प्रदेश के लिए निर्यात रणनीति' का विमोचन

एक्ज़िम बैंक ने मध्य प्रदेश सरकार के लिए 'मध्य प्रदेश के लिए निर्यात रणनीति' शीर्षक से एक शोध अध्ययन प्रकाशित किया है। अध्ययन का विमोचन मध्य प्रदेश के माननीय राज्यमंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, श्री संजय सत्येंद्र पाठक द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री वी.एल. कांता राव, प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग विशेष रूप से उपस्थित रहे। शोध अध्ययन में मध्य प्रदेश से निर्यात की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य से निर्यात संवर्धन के लिए रणनीतियां भी चिह्नित की गई हैं।

अध्ययन में राज्य के पिछले निर्यात निष्पादन की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच राज्य से निर्यात में 1.7 प्रतिशत की औसत सालाना वृद्धि दर्ज की गई और निर्यात बढ़कर 4.4 अरब यूएस डॉलर का हो गया। उल्लेखनीय है कि यह वृद्धि भारत से समग्र निर्यातों की वृद्धि से अधिक है, जिसमें इसी अवधि के दौरान गिरावट दर्ज की गई।

किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों के लिए प्रमुख निर्धारकों में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, वैश्विक तरलता और अनिश्चितता के लिए संभावनाएं शामिल होती हैं। मुद्रास्फीति रुझान खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति, जिन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापा जाता है, लगातार दूसरे महीने बढ़कर अप्रैल 2018 में 4.6 प्रतिशत से मई 2018 4.9 प्रतिशत रहे। खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने में 2.8 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर मई 2018 में 3.1 प्रतिशत रही। फ्यूल एंड लाइट ग्रुप में मुद्रास्फीति ने पिछले महीने के 5.2 प्रतिशत से बढ़कर मई 2018 में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रास्फीति के लिए अपने पूर्वानुमानों को संशोधित किया है और 2018-19 की दूसरी छमाही के 4.4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति के अनुमानों को बढ़ाते हुए इसे 4.9 प्रतिशत कर दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि इस संशोधन के मुख्य कारकों में से एक है ।

आर्थिक विकास

भारत का वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2016-17 में 7.1 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा। सेवा क्षेत्र के विकास में तेजी देखी गई। दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में विकास दर 2016-17 के 6.3 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 में कम होकर 3.4 प्रतिशत पर रही। वहीं खनन गतिविधि की वृद्धि में भी तेजी से गिरावट आई और यह 13.0 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रही। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 7.9 से 5.7 प्रतिशत और बिजली 9.2 से 7.2 प्रतिशत रही। निर्माण क्षेत्र ने अपनी वृद्धि में उल्लेखनीय छलांग लगाते हुए 2016-17 में 1.3 प्रतिशत वृद्धि से वर्ष 2017-18 के दौरान 5.7 प्रतिशत वृद्धि की। आरबीआई के अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के 2018-19 में 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो क्षमता उपयोग और ऋण उठाव में सुधार के बाद मजबूत निवेश गतिविधि द्वारा समर्थित होगी। आरबीआई के अनुमानों के अनुसार यह बढ़ती वैश्विक मांग के चलते निर्यात को प्रोत्साहित करने और निवेश को बढ़ावा देने का काम करेगी। हालांकि आरबीआई को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की आशंका है, जिससे लोगों की खर्च योग्य आय प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, किन्तु आरबीआईबैंक को देश की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के लगातार बढ़ने की उम्मीद है।

कृषि और ग्रामीण आय: कृषि सहयोग व कृषक कल्याण विभाग द्वारा 2017-18 के लिए जारी, तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न अनाज उत्पादन 279.51 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले साल की तुलना में 1.6 प्रतिशत अधिक है।

औद्योगिक उत्पादन: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के रूप में आकलित औद्योगिक गतिविधि, पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल 2018 के दौरान 4.9 प्रतिशत अधिक थी। उद्योगों के संदर्भ में, विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 15 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मार्च 2018 महीने के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी। विनिर्माण उत्पादन अप्रैल 2018 में 5.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

निजी उपभोग: निजी उपभोग, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक है, में 2017-18 के दौरान 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बीएसई-CMIEUMich सूचकांक के रूप में जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता भावना में मई 2018 में लगातार तीसरे महीने के लिए सुधार हुआ है।

निवेश: सीएमआईई कैपेक्स डाटाबेस के अनुसार, 2017-18 में 6.6 ट्रिलियन रुपए के निवेश के साथ 2,496 नई परियोजनाओं की घोषणा की गई। मूल्य संदर्भ में 2016-17 की तुलना में ये 52 प्रतिशत तक कम थे। निवेश ठप हो गया क्योंकि व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं थी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी औद्योगिक सर्वेक्षण के अप्रैल-जून के शुरुआती परिणामों के अनुसार, समग्र कारोबारी स्थिति और ऑर्डर बुक में गिरावट के कारण विनिर्माण क्षेत्र में गतिविधि 2018-19 की दूसरी तिमाही में केवल मामूली रूप से बढ़ने की उम्मीद है।

वैश्विक तरलता

वास्तविक आर्थिक आंकड़ों में सुधार के लिए वैश्विक तरलता और जारी मजबूत श्रम बाजार लाभ के चलते फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) ने संघीय ब्याज दर को जून 2018 में 25 बीपीएस से बढ़ाकर 1.75 -2.00 प्रतिशत की लक्ष्य सीमा तक कर दिया। अमेरिकी फेड दर में वृद्धि के साथ वैश्विक तरलता के प्रभावित होने और धन के पुनर्आवंटन की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दर अंतर से आकर्षित विदेशी पूँजी से देश को जबरदस्त लाभ हुआ, किन्तु अब अमेरिका में दरों में लगातार वृद्धि से निवेशकों को भारत से कैरी ट्रेड के लिए उधारियों की लागत बढ़ेगी और जोखिम समायोजित रिटर्न कम प्राप्त होगा, इस प्रकार अब भारत में निवेश विदेशी निवेशकों के लिए उतना आकर्षक नहीं रहेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक की दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 में मौद्रिक नीति समिति ने लिक्विडि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 6.25 प्रतिशत कर दिया है। अमेरिका में दरों में लगातार बढ़ोतरी के कारण पूँजी के जावक प्रभाव को कम करने और रुपए पर आगामी दबाव के चलते घरेलू ब्याज दरों के और बढ़ने की संभावना है। फेड दर में वृद्धि, व्यापार तनाव और व्यापक आर्थिक चिंताएं एक साथ मिलकर पहले से ही भारत में विदेशी संस्थागत निवेश को प्रभावित कर रही हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार, 2018 में अब तक विदेशी निवेशकों ने लगभग ₹ 6,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण मूल्य की इक्विटी और ₹ 41,000 करोड़ से अधिक ऋण बेच दिया, जो 2009 के बाद से सबसे खराब बहिर्वाह रहा।

संभावनाएं

मुद्रास्फीति 2018-19 में मध्यम रहने की उम्मीद है। मजबूत निजी उपभोग, निर्यात और बुनियादी ढांचा निवेश में बढ़ोत्तरी के चलते आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि यूएस फेड दरों में वृद्धि के चलते पूँजी प्रवाह में कमी और मैक्रो इकोनोमिक स्थितियों की अनिश्चितता रुपए पर दबाव डाल रही है। इन घटनाओं को देखते हुए, विशेष रूप से उच्च तेल की कीमतों से मुद्रास्फीति के दबाव के चलते आरबीआई द्वारा, रेपो दर में और वृद्धि किए जाने की उम्मीद है।

मार्केटिंग सलाहकारी गतिविधियां

बांस और बेंत विकास संस्थान, अगरतला और नॉर्थ ईस्ट हस्तशिल्प, असम के सहयोग से एक्ज़िम बैंक, हाल ही में असम के बारपेटा जिले में बांस और बेंत कारीगरों के लिए एक डिजाइन विकास और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य कारीगरों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए नए उत्पादों को डिजाइन करने के लिए सक्षम बनाना था। कार्यशाला में कारीगरों को कच्चे माल के सही इस्तेमाल और व्यापक अपील वाले नए उत्पादों के विकास के लिए नवोन्मेषी तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

एक महीने की अवधि वाली इस कार्यशाला का आयोजन बांस क्राफ्ट में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्री मनेन्द्र डेका, द्वारा बारपेटा में स्थापित एक सुविधा में किया गया था। कार्यक्रम के दौरान कुल 200 उत्पादों के प्रोटोटाइप का विकास किया गया, जिसे क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर पूर्वी क्षेत्र), कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) और जिला आयुक्त बारपेटा के द्वारा सराहा गया। इसी प्रकार के अन्य प्रयास में, बैंक ने एक ई-कॉमर्स कंपनी के सहयोग से राजस्थान में सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग के कारीगरों को सहयोग प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्पादों के कलात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए एक उत्तम संग्रह बनाने के उद्देश्य से सांगानेर, राजस्थान में 10 कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ई-कॉमर्स कंपनी के वरिष्ठ डिजाइनरों द्वारा कारीगरों को डिजाइन इनपुट और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रतिभागियों (मास्टर कारीगरों और बुनकरों) ने कार्यक्रम के दौरान कई नमूना प्रोटोटाइप तैयार किए, जिसके आधार पर बड़ी संख्या में उत्पादों को विकसित किया जाएगा। ये उत्पाद ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगें। इस प्रकार कारीगरों को एक नए प्रकार के बाजार तक पहुँचने का अवसर मिलेगा।

एक्ज़िम बैंक अपनी विपणन सलाहकारी सेवाओं के माध्यम से, भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक संवर्धक की भूमिका निभाता है। बैंक निर्यातकों के लिए विदेशों में अवसरों की पहचान करने और उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए विदेशी वितरकों/ खरीदारों/ भागीदारों का पता लगाने में सक्रिय रूप से सहायता कर भारतीय निर्यातक कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों में उनकी मदद करता है। बैंक कौशल विकास, उत्पाद विकास और निर्यात क्षमता जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग प्रदान कर ग्रासरूट उद्यमों को बढ़ावा देता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें: mas@eximbankindia.in

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र की गतिविधियां

एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित सेमिनार और कार्यशालाएं

भारत के विभिन्न शहरों में सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए भारतीय एक्ज़िम बैंक ने कई उद्योग संघों के साथ साझेदारी की है। बैंक ने एसोचैम के सहयोग से कोलकाता, अहमदाबाद और नई दिल्ली में 'ट्रेड फायनेंस फॉर इंफॉर्मेशन ग्रोथ' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। इस क्षेत्र के निर्यातक समुदाय के लाभ के लिए कोयंबटूर में सीआईआई के साथ मिलकर एक निर्यात क्लिनिक का आयोजन किया गया। विश्व व्यापार दिवस के उपलक्ष्य में विश्व व्यापार केंद्र (मुंबई) और एक्ज़िम बैंक ने संयुक्त रूप से 'निर्यात बाजार में एमएसएमई के लिए अवसर' थीम पर महाराष्ट्र में सेमिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इन सेमिनारों का आयोजन नासिक, अहमदनगर, कोल्हापुर, इचलकरंजी और नागपुर में किया गया। इन सेमिनारों में मुख्य रूप से इस क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयों की निर्यात क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक्ज़िम बैंक ने कोलकाता में 'एडीबी-वित्तपोषित परियोजनाओं' में कारोबार के अवसरों पर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया।

भारतीय निर्यातकों के संगठन फिओ के साथ मिलकर एक्ज़िम बैंक ने जालंधर में 'पंजाब से निर्यात की संभावनाओं और व्यापार अवसर' पर एक चर्चापरक बैठक का आयोजन किया। जालंधर पंजाब के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है और 2016-17 में कुल निर्यात में इसका 2265.5 करोड़ रुपए का योगदान रहा है। यह शहर स्पोर्ट्स गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हब है और एशिया में स्पोर्ट्स गुड्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। उद्योग मंत्रालय, पंजाब सरकार, कराधान विभाग, ई सी जी सी लिमिटेड, विदेश व्यापार महानिदेशालय और एक्ज़िम बैंक से आए वक्ताओं ने पंजाब के व्यापारियों, निर्माताओं और कारोबारियों के साथ अपने अनुभव और जानकारी साझा की।

एक्ज़िम बैंक द्वारा आयोजित सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करें www.eximbankindia.in/upcoming-events.

नई पहल

एक्ज़िम बैंक ने अपने आंतरिक एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स मॉडल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2018 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले भारत के कुल वस्तु निर्यातों में 10.6 प्रतिशत तथा गैर-तेल निर्यातों में 6 प्रतिशत की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान एक्ज़िम बैंक के एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ई एल आई) मॉडल पर आधारित है, जिसमें कुल वस्तु निर्यातों और गैर-तेल निर्यातों की वृद्धि क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत रही। भारत के कुल वस्तु निर्यातों और गैर-तेल निर्यातों में वृद्धि का पूर्वानुमान हर तिमाही आधार पर संबंधित तिमाही के लिए जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा और इस मॉडल में भी निरंतर सुधार का प्रयास किया जाता रहेगा। जुलाई-सितंबर 2018 तिमाही के लिए भारत के निर्यातों में वृद्धि का पूर्वानुमान सितंबर 2018 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। इस मॉडल तथा इससे प्राप्त पूर्वानुमान संबंधी परिणामों की समीक्षा विशेषज्ञों की एक स्थाई तकनीकी समिति द्वारा की गई है। इस समिति के सदस्यों में प्रोफेसर सैकत सिन्हा रॉय, प्रोफेसर एवं संयोजक, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, अर्थशास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता; डॉ. सरत धल, निदेशक, अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता; प्रोफेसर एन.आर. भानुमूर्ति, प्रोफेसर, नेशनल इंडस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फायनेंस एंड पॉलिसी (एन आई पी एफ पी), नई दिल्ली तथा प्रोफेसर सी. वीरामणि, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आई जी आई डी आर), मुंबई शामिल हैं।

एक्ज़िम बैंक द्वारा अपने निरंतर शोध प्रयासों की कड़ी में भारत के निर्यातों का तिमाही आधार पर ट्रैक रखने तथा वृद्धि में पूर्वानुमान के लिए एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ई एल आई) तैयार करने हेतु यह इन-हाउस मॉडल विकसित किया गया है। इस इंडेक्स को देश के निर्यातों पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न बाह्य एवं घरेलू कारकों को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को देश के वस्तु निर्यातों में तिमाही आधार पर वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में विकसित किया गया है।

इथियोपिया

एक अनुमान के अनुसार इथियोपिया के जीडीपी की वृद्धि दर वर्ष 2017 में 9.1% रही, जबकि 2016 में यह 7.6% थी। यह वृद्धि दर मुख्यत: कृषि क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक निवेश से प्रेरित रही। मुद्रा के अवमूल्यन, जारी सूखा स्थितियों और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतों से होने वाले दबाव के साथ औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2017 में 9.8% पर रही, जबकि 2016 में यह 7.3% थी। इथियोपिया के राष्ट्रीय बैंक द्वारा पुनर्मूल्यांकन को कम करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए बिर (इथियोपिया की स्थानीय मुद्रा) को अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष अक्टूबर 2017 में 15% तक अवमूल्यित किया गया। बिर के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 2017 में एक यूएस डॉलर के मुकाबले बिर की कीमत 23.95 हो गई, जबकि वर्ष 2016 में यह 21.73 थी। इसके चलते इथियोपिया का चालू खाते का घाटा थोड़ा बढ़ा और 2016 के 8.3 अरब यूएस डॉलर (जीडीपी का 11.4%) की तुलना में 2017 में 8.4 अरब यूएस डॉलर (जीडीपी का 11.8%) रहा। कृषि विस्तार में अवरोधों और छोटे भूधारकों द्वारा न्यून उत्पादकता के चलते इथियोपिया की रियल जीडीपी वृद्धि दर भी घटकर 2018 में 7.6% और 2019 में 7.1% रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बिर का प्रबंधन कड़ी निगरानी में किया जाता रहेगा और बिर के अवमूल्यन का पैटर्न उसी प्रकार बने रहने की संभावना है। इसके चलते 2018 में एक यूएस डॉलर के मुकाबले बिर का मूल्य 27.75 और 2019 में 28.95% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही बढ़ते विनिर्माण क्षेत्र के लिए मशीनरी आदि के आयात मूल्य में बड़ी वृद्धि से उत्पन्न व्यापार घाटे से चालू खाते का घाटा भी बढ़कर 2018 में 9.3 अरब यूएस डॉलर (जीडीपी का 12.8%) रहा।

ईरान

गत वर्ष के तेल उत्पादन और निर्यात में पिछले साल की बढ़ोत्तरी के प्रभाव के समाप्त होने से ईरान के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2016 की 11.4% की तुलना में घटकर 2017 में 3.5% रहना अनुमानित है। औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 8.7% से बढ़कर 2017 में 10% हो गई जो उच्च खाद्य कीमतों और धीरे-धीरे बढ़ती मांग को प्रतिबिंबित करता है।

ईरानी मुद्रा रियाल के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 2017 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 2017 में 33,226 हो गई, जबकि वर्ष 2016 में यह 30,915 थी। इसके चलते इथियोपिया का चालू खाते का अधिशेष बढ़ा और 2016 के 16.4 अरब यूएस डॉलर (जीडीपी का 3.9%) की तुलना में 2017 में 18 अरब यूएस डॉलर (जीडीपी का 4.1%) रहा। आगामी 6 महीनों (अगस्त से नवंबर 2018) के अंदर संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान को अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनमें ईरान के तेल निर्यात में कमी के साथ ही निवेशकों और उपभोक्ताओं के विपरीत रुझानों की संभावना शामिल है। इसके चलते वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के भी घटकर 2018 में 1.9% और 2019 में -2.6% रहने का पूर्वानुमान है। परमाणु समझौते के संभावित प्रभावों के लंबा खिंचने से रियाल के और कमजोर होने तथा ईरान की आधिकारिक विनिमय दर भी 2018 में 1 यूएस डॉलर के बदले 40,536 रियाल और 2019 में 49,454 रियाल हो जाने का अनुमान है। तथापि, पिछले साल की तुलना में इस साल तेल की कीमतों में तेजी और उपभोग तथा निवेश संचालित मांग में कमी के चलते आयातों में गिरावट आने तथा तदनुसार 2018 तथा 2019 में भी ईरान में व्यापार अधिशेष बने रहने की संभावना है। परिणामत: वर्ष 2018 में चालू खाते का घाटा औसतन 25.2 अरब यूएस डॉलर (जीडीपी का 6%) रहने की संभावना है।

सऊदी अरब

ओपेक द्वारा तेल उत्पादन कमी के चलते सऊदी अरब की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2016 की 1.4% की तुलना में घटकर 2017 में 0.7% रही है। औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 2.9% से घटकर 2017 में -0.8% हो गई। सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल 2017 में 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 3.75 थी। सऊदी अरब का चालू खाते का घाटा 2016 के 23.8 अरब यूएस डॉलर (जीडीपी का 3.7%) की तुलना में 2017 में 15.3 अरब यूएस डॉलर (जीडीपी का 2.2%) रहा ।

सऊदी अरब के वास्तविक जीडीपी के 2018 में 1% की एक सकारात्मक विकास दर पर लौटने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से गैर-तेल गतिविधि, जैसे सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्र में गतिविधियों के उठाव से संचालित होगी। इसके साथ ही तेल की कीमतों में तेजी की संभावना के चलते निवेशक विश्वास ठीक रहेगा और यह अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित संचालक के रूप में बना रहेगा। ताजा ईंधन और बिजली सब्सिडी में कटौती जो सामान्य मूल्य स्तरों और विशेष रूप से वैट के प्रभाव को समायोजित कर देने के चलते मुद्रास्फीति की दर के 2018 में 4.4% की औसत दर पर बने रहने की उम्मीद है। तेल उत्पादन के विस्तार और एल्यूमीनियम, फॉस्फेट और पेट्रो रसायन के बढ़ते निर्यात की मात्रा से समर्थित चालू खाते के सकल घरेलू उत्पाद के 7% अधिशेष के स्तर पर बने रहने की संभावना है।

तुर्की

बढ़ती वैश्विक मांग, सरकारी प्रोत्साहनों और उपायों, सार्वजनिक ऋण और गारंटियों तथा बैंकों पर ऋण देने के राजनीतिक प्रभावों के चलते तुर्की की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2016 की 3.3% की तुलना में बढ़कर 2017 में 7% रही है। तुर्की की औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 7.8% से बढ़कर 2017 में 11.1% हो गई (जो केंद्रीय बैंक के मध्यावधि लक्ष्य 5% से काफी अधिक है)। यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से टर्किश लीरा के कमजोर होने के चलते जो 2016 में 1 डॉलर के मुकाबले 3 लीरा से बढ़कर 2017 में 3.6 टर्किश लीरा हो गई। तुर्की का चालू खाते का घाटा भी 2016 के 32.6 अरब यूएस डॉलर (जीडीपी का 3.8%) की तुलना में बढ़कर 2017 में 42.4 अरब यूएस डॉलर (जीडीपी का 5.0%) रहा। टैक्स दरों में बढ़ोत्तरी, ऊंची ब्याज दरों, जुलाई 2016 में हुए विद्रोह के बाद सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए शुरू किए गए प्रोत्साहक उपायों की वापसी तथा वैश्विक लिक्विडिटी में कमी के चलते तुर्की की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के कम होकर 4.2% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही वास्तविकता में मुद्रा के स्थिर रहने के चलते तुर्किश लीरा के अवमूल्यन की दर भी 2018 में मंद हो जाने का अनुमान है। तुर्किश लीरा के अवमूल्यित रहकर 2018 में औसतन 1 यूएस डॉलर के बदले 3.845 तुर्किश लीरा पर बने रहने का अनुमान है। कमजोर लीरा तथा रूस द्वारा लगाए प्रतिबंधों के हटाने के चलते तुर्की के निर्यातों के बढ़ने की उम्मीद है। तथापि यदि वैश्विक तरलता की स्थिति तंग बनी रहती है और निवेशकों का उत्साह कम रहता है तो तुर्की की बाहरी वित्तपोषण जरूरतों के प्रभावित होने की आशंका है।

स्विस फ्रैंक

हाल के सप्ताहों में लगभग 1.155 पर मजबूत स्थिति दर्ज कराने के बाद स्विस फ्रैंक इस साल फिर से यूरो के बदले 1.20 के प्रतीकात्मक स्तर पर कमजोर स्थिति में रहा।

जून के दौरान, स्विस फ्रैंक यूरो की तुलना में लगभग 0.3% प्रतिशत कमजोर रहने के बाद 1.162 के स्टार पर रहा। क्योंकि स्विट्जरलैंड में मतदाताओं द्वारा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार दिए जाने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा बनाने संबंधी स्विट्जरलैंड के वित्तीय परिदृश्य को बदलने की योजना को खारिज कर दिया गया। स्विस नेशनल बैंक ने इस पहल का विरोध किया था, जो स्विट्जरलैंड में मुद्रा छापने की एक नई संस्था बना दिया होता। उसका कहना था कि इससे इसकी मौद्रिक नीति का संचालन करने की क्षमता प्रभावित होती। विश्लेषकों का तर्क था कि इस पहल की स्वीकृति से फ्रैंक पर ऊपर बढ़ने का दबाव पड़ता क्योंकि कमजोर मुद्रा बाजार में एसएनबी की हस्तक्षेप करने की क्षमता के चलते सट्टेबाजों द्वारा एक नई मुहिम शुरू की जा सकती थी। एसएनबी ने इसके परिणाम को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पहल ने स्विट्जरलैंड में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बहुत कठिन बना दिया होता।

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर न केवल बेहतर स्थिति में बना रहा, बल्कि पिछली तिमाही की आशाओं के अनुरूप इसने काफी अच्छा निष्पादन किया। वर्ष 2017 के अंत से ही डॉलर न केवल वाशिंगटन में अव्यवस्था के डर, बल्कि देश के बाहर स्थितियों में बेहतरी के संबंध में निवेशकों के रुझान के चलते कमजोर प्रदर्शन कर रहा था। अमेरिकी डॉलर में हालिया उछाल अचानक आया है। इसके पीछे शुरुआती तौर पर परिस्थिति-जन्य समायोजन हो सकते हैं; किन्तु बाद में इसमें यूरोप की राजनैतिक चिंताओं और अमेरिका के व्यापारिक भागीदारों के बीच चल रही व्यापार विवादों की प्रमुख भूमिका रही।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार रिज़र्व करेंसी के रूप में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा 2018 की पहली तिमाही में घटकर 4 वर्ष के सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया। रिज़र्व करेंसी के रूप में अमेरिकी डॉलर का यह हिस्सा पाँच तिमाहियों से लगातार घट रहा है। अमेरिकी डॉलर 2018 के पहले तीन महीने के दौरान कमजोर हुआ, जिसका प्रमुख कारण यूएस से बाहर तेज वृद्धि की उम्मीदों के चलते यह अपेक्षा थी कि अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रोत्साहन वापस लिया जाएगा। हालांकि अभी भी अमेरिकी डॉलर सबसे बड़ी रिज़र्व करेंसी बनी हुई है। किन्तु दूसरी तिमाही से अमेरिकी डॉलर ने मजबूती दिखानी शुरू की, जिसका कारण वैश्विक व्यापार विवाद और यूरोपीय केंद्रीय बैंक की यह घोषणा रही कि उनके द्वारा 2019 की दूसरी छमाही तक दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी।

जून 2018 के दौरान अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (यह यूरो, येन, स्टर्लिंग और अन्य तीन प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले ग्रीनबैक की स्थिति को ट्रैक करता है) 95.31 पर पहुंच गया, जो गत वर्ष के जुलाई से सबसे ऊंचा स्तर है। इसी प्रकार पीसीई इंडेक्स, जो यूएस में मुद्रास्फीति नापने के लिए फेडरल रिज़र्व का सबसे पसंदीदा इंडेक्स है, भी पिछले साल 2.00 प्रतिशत बढ़ा, जो अप्रैल 2012 के बाद से सबसे बड़ा उछाल है। इससे यह उम्मीद बढ़ी कि फेड द्वारा साल के अंत तक कम से कम एक बार या दो बार फेड दरों में बढ़ोत्तरी जरूर की जाएगी। हालांकि

निवेशक डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा चलाए गए व्यापार संरक्षण विवाद और अमेरिका फर्स्ट जैसी नीति से चिंतित रहे। इसके साथ ही अमेरिका द्वारा 450 बिलियन यूएस डॉलर चीनी आयात पर ड्यूटी लगाने की धमकी भी है जिसके 34 बिलियन यूएस डॉलर के पहले हिस्से को 6 जुलाई को प्रभावी होना है।

जापानी येन

अमेरिकी डॉलर येन के मुकाबले काफी चढ़ा और यह जून 2018 में 110.09 येन के स्तर पर पहुंच गया। जापानी येन बैंक ऑफ जापान के इस सर्वे, जिसमें कहा गया था कि बड़ी जापानी विनिर्माण गतिविधियों में गिरावट आएगी, से पूरी तरह अप्रभावित रहा।

जापानी येन विश्व के वित्तीय और भूराजनीतिक परिदृश्य में आए तनाव से लाभदायक स्थिति में रहेगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा क्रेडिटर राष्ट्र है और यह माना जाता है कि किसी भी संकट की स्थिति में जापान के निवेशक अपना पैसा वापस निकाल लेंगे।

हालांकि जापानी येन अस्थाई तौर पर निवेशकों के लिए सुरक्षित मुद्रा बनकर उन्हें आकर्षित करता रहेगा किन्तु भू-राजनैतिक हलचलों और व्यापार जोखिमों के चलते क्षेत्रीय मुद्राओं की संभावनाओं के धूमिल बने रहने की आशंका है। बढ़ती ब्याज दरों और कड़ी मौद्रिक दशाओं के चलते अधिक ऋणग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष कठिनाई आने की संभावना है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्थाएं अपनी ऋण जरूरतों के लिए निवेशकों की तलाश में प्रतिस्पर्धा कर रही होंगी, जबकि निवेशक उन मुद्राओं / देशों में अपने निवेश बनाए रखने का प्रयास करेंगे, जिनका प्रदर्शन हाल के महीनों में अच्छा रहा है।

संकेतक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर, बिलियन यूएस डॉलर)	1874.3	1863.6	1919.4	2043.3	2147.2[f]	2271.0[f]	2585.0[f]
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (यू एस डॉलर)	6.7	5.5	6.4	7.5	8.0	7.1[p]	6.7[f]
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	18.5	18.3	18.6	18.0	17.5	17.4[re]	17.1[re]
उद्योग	32.5	31.7	30.8	30.2	29.6	28.8[re]	29.1[re]
सेवाएँ	49.0	50.0	50.6	51.8	52.9	53.8[re]	53.8[re]
मुद्रास्फीति दर (सीपीआई, वार्षिक औसत %)	8.3	10.2	9.5	5.9	4.9	3.8	3.6
मुद्रास्फीति दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	8.9	7.4	6.0	2.0	–2.5	1.7	2.8
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5[e]	3.5[e]
विनिमय दर (₹ / यूएस डॉलर, औसत)	47.9	54.4	60.5	61.1	65.5	67.1	64.4
विनिमय दर (₹ / यूरो, औसत)	65.9	70.1	81.2	77.5	72.3	73.6	72.1
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	306	300.4	314.4	310.3	262.3	276.5	303.3
%परिवर्तन	22.5	–1.8	4.7	–1.3	–15.5	5.4	9.9^
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	56.7	60.9	63.2	56.7	30.6	31.6	37.4
%परिवर्तन	55.9	7.3	3.8	–10.2	–46.1	3.4	18.5^
गैर– तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	249.2	239.5	251.2	253.6	231.7	244.9	265.9
%परिवर्तन	16.8	–3.9	4.9	0.9	–8.6	5.7	8.7^
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	489.3	490.7	450.2	448	381	382.7	464.7
%परिवर्तन	32.3	0.3	–8.3	–0.5	–15	0.5	20.9^
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	155	164	164.8	138.3	82.9	86.9	108.6
%परिवर्तन	46.2	5.9	0.4	–16	–40	4.7	24.9^
गैर– तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	334.3	326.7	285.4	309.7	298.1	295.9	356.1
%परिवर्तन	26.7	–2.3	–12.6	8.5	–3.8	–0.7	19.7^
व्यापार शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	–183.3	–190.3	–135.8	–137.7	–118.7	–106.2	–161.4
सेवा निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	140.9	145.7	151.8	158.1	154.3	163.1	195.1
सॉफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	62.2	65.9	69.4	73.1	74.2	73.7	77.3
सेवा आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	76.9	80.8	78.7	81.6	84.6	95.7	117.5
सेवा संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)	64	64.9	73.1	76.5	69.7	67.4	77.6
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	–78.2	–87.8	–32.4	–26.8	–22.1	–15.2	–48.7
डीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष (%)	–4.2	–4.8	–1.7	–1.3	–1.1	–0.7	–1.9
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	294.4	292	304.2	341.6	360.2	370	424.4
विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	360.8	409.4	446.2	474.7	484.8	471.3	529.7
जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण अनुपात (%)	20.5	22.3	23.9	23.2	23.4	20.2	20.5
अल्पावधि ऋण (यूएस बिलियन डॉलर)	78.2	96.7	91.7	85.5	83.4	88	102.2
अल्पावधि ऋण / कुल ऋण (%)	21.7	23.6	20.5	18	17.2	18.6	19.3
कुल ऋण चुकौती अनुपात (%)	6	5.9	5.9	7.6	8.8	8.3	7.5
एफ़डीआई (बिलियन यूएस डॉलर)	46.6	34.3	36	45.1	55.6	60	61.0
जीडीआर/एडीआर (बिलियन यूएस डॉलर)	0.6	0.2	0.02	1.3	0.4	–	–
एफ़आईआई (नेट) (बिलियन यूएस डॉलर)	16.8	27.6	5	40.9	–4	7.7	22.2
एफ़डीआई जावक (बिलियन यूएस डॉलर)	10.9	7.1	9.2	4	8.9	7	9.3

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक; केंद्रीय बजट, आरबीआई मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट और साप्ताहिक सांख्यिकी सप्लीमेंट, वित्त मंत्रालय; सीएसओ; ईआईयू; नैसकॉम; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ़) डबल्यूईओ; आईएमएफ।

नोट: e–भारत सरकार के अनुमान; re– संशोधित आकलन, ae– अग्रिम अनुमान; f–आई आई एफ पूर्वानुमान; – उपलब्ध नहीं; – ^–% गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन;

9 जून, 2018 को अपडेट

व्यापार और भागीदारी अवसर

व्यापार अवसर

सिंचाई

भारत में ड्रिप सिंचाई सिस्टम, स्मार्ट सिंचाई समाधानों और इंस्टॉलेशन की अग्रणी विनिर्माता। 1997 में भारत में तीन विनिर्माण संयंत्रों के साथ स्थापित यह कंपनी अलग-अलग कृषि-जलवायु वाले क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त 20 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर सफलतापूर्वक संचालनरत है।

हस्तशिल्प उद्यम

प्राकृतिक और शिल्प आधारित आधुनिक उत्पाद बनाने वाला विनिर्माण उद्यम। उद्यम द्वारा वर्तमान में, विभिन्न ग्रामीण क्लस्टरों से आने वाले एक हजार से ज्यादा शिल्पकारों के हाथों से बने 300 से अधिक उत्पादों की देशभर में आपूर्ति की जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण शिल्पकारों का कौशल विकास और उन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध कराते हुए भारत के परंपरागत हस्तशिल्पों का संरक्षण करना है।

दुग्ध उत्पाद

किसानों की मदद करने के उद्देश्य से दो दशक पहले स्थापित यह कंपनी आज एक जानी-मानी और गुणवत्तापूर्ण दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के लिए जानी जाती है। वर्तमान में कंपनी द्वारा खुदरा बाजार में स्किम्ड दुग्ध पाउडर, पूर्ण दुग्ध पाउडर और घी की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही यह दुग्ध उत्पादों की एक प्रमुख भारतीय और अंतरराष्ट्रीय विनिर्माता कंपनी है।

माचिस

अत्याधुनिक तकनीक से लैस विभिन्न तरह की माचिसों की विनिर्माता। कंपनी उच्च मानकों का अनुपालन करती है और अलग-अलग आकार की माचिसें बनाकर ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहती है। कंपनी ने विभिन्न देशों से उठती मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक बाजार में कदम रखा है।

पेयजल

एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी। कंपनी ने भारत के 36 जिलों में 450 से ज्यादा विकेंद्रीकृत सामुदायिक पेयजल सिस्टम सफलतापूर्वक इंस्टॉल किए हैं और उनका परिचालन कर रही है। कंपनी का तुरंत चालू होने वाला सिस्टम किसी भी उपलब्ध जल स्रोत से पानी को शुद्ध करता है और गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का त्वरित और सुरक्षित समाधान प्रदान करता है।

ऊनी कपड़े

महिलाओं की एक सहकारी संस्था, जो हाथों से बुने ऊनी कपड़े बनाती है। कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में पश्मीना (कश्मीरी) ऊन, याक ऊन और ऊंट की ऊन शामिल है। संस्था पश्मीना के प्राकृतिक रंगों को संरक्षित रखती है और इसके उत्पादों में एसेसरीज़ से लेकर दस्ताने, स्कार्फ, शॉल, नेक वार्मर, टोपियां, जुराबें और स्वेटर आदि शामिल हैं।

भागीदारी अवसर

परियोजना अवसर

(I) ने पी तॉ डेवलपमेंट कमेटी (एनपीटीडीसी) द्वारा निजी स्वामित्व वाली ईंट फैक्टरी के लिए निम्नलिखित उत्पादों के लिए खुला टेंडर आमंत्रित किया गया है:

(क) वीसीबी (वैक्यूम सर्किट ब्रेकर) (फ्रीक्वेंसी 50Hz, वोल्टेज 12केवी, नॉर्मल करंट 630A, शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट 25kA)। उक्त टेंडर के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 06.07.2018 है।

निर्यात अवसर

(I) म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय ने 25/2018 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें म्यांमार में थोक का कारोबार करने के लिए विदेशी कंपनियों और स्थानीय तथा विदेशी निवेशकों के बीच संयुक्त उद्यमों की अनुमति दी गई है।

(II) आइवरी कोस्ट से एक आयातक 120 दिन की ऋण अवधि पर माचिस आयात करने का इच्छुक है। वर्ष में 7-8 कंटेनरों की आपूर्ति करने की आवश्यकता है। इच्छुक निर्यातक नीचे उल्लिखित विवरण के जरिए मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं से संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: फोन: 2217 2600, एक्सटेंशन: 2822/2737, फैक्स: 2218 8268, ईमेल: mas@eximbankindia.in